


**उत्तराखण्ड शासन**  
**कार्मिक अनुभाग-2**  
**संख्या 9/6/XXX (2)/2012**  
**देहरादून दिनांक 19 सितम्बर, 2012**

**कार्यालय ज्ञाप**

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 903/XXX(2)/2012 दिनांक 05 सितम्बर, 2012 के द्वारा मा. न्यायमूर्ति (से.नि.) श्री इरशाद हुसैन की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय आयोग गठित किया गया है।

2. मा. न्यायमूर्ति (से.नि.) श्री इरशाद हुसैन को वेतन/भत्ते तथा आयोग को अपने कार्य सम्पादन हेतु निम्नानुसार सुविधाएं सुलभ होंगी :-

- (1) आयोग के कार्यकाल के दौरान आयोग के मा. अध्यक्ष को मा. उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायमूर्ति को देय वेतन एवं अन्य आनुसंगिक भत्ते अनुमन्य होंगे जिसका भुगतान इरला चैक द्वारा किया जायेगा।
  - (2) आयोग के मा. अध्यक्ष द्वारा कार्य सम्पादन में सहयोग हेतु आवश्यक संख्या में विशेषज्ञ आबद्ध किए जा सकेंगे और आबद्ध किए गए विशेषज्ञों को शासन द्वारा वह मानदेय एवं अन्य सुविधाएं अनुमन्य की जायेंगी जिनका निर्धारण आयोग के अध्यक्ष के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। इस मद में होने वाले व्यय का भुगतान इरला चैक के द्वारा किया जायेगा।
  - (3) शासन द्वारा आयोग को कार्य सम्पादन हेतु आयोग के मा. अध्यक्ष से परामर्श करने के उपरान्त एक कार्यालय (दूरभाष/फैक्स सुविधा सहित) तथा आवश्यक लेखन सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी।
  - (4) कार्य सम्पादन में सहयोग हेतु आयोग का एक सचिव होगा तथा मा. अध्यक्ष को एक निजी सचिव, एक टंकक/कम्प्यूटर आपरेटर तथा दो अनुसेवक उपलब्ध कराये जायेंगे। इस निमित्त संविदा के आधार पर सचिव पद हेतु अधिकतम ₹ 80,000/- निजी सचिव पद हेतु अधिकतम ₹ 25,000/-, टंकक/कम्प्यूटर आपरेटर पद हेतु अधिकतम ₹ 15,000/- तथा अनुसेवक पद हेतु अधिकतम ₹ 10,000/- मासिक नियत वेतन के आधार पर अस्थाई पदों का सृजन आयोग के कार्यकाल तक के लिए किया जायेगा। सृजित पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी, किन्तु यह संभव न हो पाने की दशा में इन पदों के सापेक्ष तैनाती आयोग के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियमित कार्मिकों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जायेगी और प्रतिनियुक्ति पर तैनाती की दशा में सम्बन्धित नियमित कार्मिक को अपने पैतृक विभाग में धारित मूल पद के वेतनमान के अनुसार वेतन का भुगतान सम्बन्धित पैतृक विभाग द्वारा किया जायेगा।
  - (5) आयोग के मा. अध्यक्ष को राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा उपलब्धतानुसार शासकीय वाहन (ईंधन एवं चालक सहित) अथवा किराए पर टैक्सी लेकर उपलब्ध कराया जायेगा।
3. आयोग के अध्यक्ष, विशेषज्ञगण तथा संविदा पर तैनात कार्मिकों को अनुमन्य वेतन/मानदेय की मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुदान संख्या-7 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2052-सचिवालय-सामान्य सेवायें-00-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-सचिवालय अधिष्ठान-16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 86 NP/XXVII(5)/2012 दिनांक 19.09.2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

  
**(डी.के. कोटिया)**  
**प्रमुख सचिव।**

संख्या 9160/XXX(2)/2012 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल को महामहिम श्री राज्यपाल के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा को मा. अध्यक्ष, विधान सभा के संज्ञानार्थ।
4. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. गठित आयोग के मा. अध्यक्ष।
6. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
7. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
8. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
12. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, इरला बैंक, उत्तराखण्ड शासन।
15. वित्त (वे.आ.-सा.नि.) अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन।
16. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)  
अपर सचिव।